CEDSI
CENTRE OF EXCELLENCE FOR DAIRY SKILLS IN INDIA

CEDSI TIMES

Your Skilling Partner...

दूध की उचित कीमतें सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश छह डेयरी संयंत्रों को एक दशक के लिए पट्टे पर देगा

उत्तर प्रदेश सरकार ने छह डेयरी संयंत्रों को दस साल की अवधि के लिए पट्टे पर देने की योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य उत्पादकों के लिए समान दूध की कीमतों की गारंटी देना और उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले दूध की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि कुछ चयनित संयंत्र वर्तमान में बंद हैं, जबकि अन्य क्षमता से कम काम कर रहे हैं। इस कदम से पीसीडीएफ (उत्तर प्रदेश सहकारी डेयरी फेडरेशन) को मजबूती मिलने और डेयरी से संबंधित विभिन्न संस्थाओं को लाभ होने की उम्मीद है। पट्टे की व्यवस्था के बावजूद, गोरखपुर, कानपुर, नोएडा, प्रयागराज, आज़मगढ़ और मुरादाबाद संयंत्रों का स्वामित्व पीसीडीएफ और दुग्ध संघों के पास रहेगा।

पट्टे पर देने वाली कंपनियाँ प्रबंधन और संचालन की देखरेख करेंगी लेकिन उन्हें संयंत्रों की मूलभूत संरचनाओं में बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वार्षिक पट्टा किराया पहले तीन वर्षों तक अपरिवर्तित रहेगा और फिर चौथे वर्ष से सालाना 5.50% की वृद्धि होगी।

इस परिवर्तन से संबद्ध दुग्ध संघों के संचालन को बनाए रखने और नियमित संयंत्र गतिविधियों की निरंतरता सुनिश्चित करने की उम्मीद है।

पशुपालन और डेयरी क्षेत्र पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठक भुवनेश्वर में आयोजित की गई

भुवनेश्वर ने पांच पूर्वी राज्यों - ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के पशुपालन और डेयरी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक क्षेत्रीय समीक्षा बैठक की मेजबानी की। भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा ओडिशा के मत्स्य पालन एवं पशु संसाधन विकास विभाग के सहयोग से आयोजित बैठक का उद्देश्य केंद्रीय क्षेत्र और प्रायोजित योजनाओं की प्रगति का आकलन करना था।

चर्चाएँ पशुधन स्वास्थ्य, रोग नियंत्रण कार्यक्रम, पशुधन मिशन, बुनियादी ढाँचे के विकास और ऋण पहल के इर्द-गिर्द घूमती रहीं। कार्यक्रम कार्यान्वयन के दौरान आने वाली चुनौतियों का समाधान किया गया, साथ ही निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासों को बढ़ाने का आह्वान किया गया। बैठक में राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के प्रतिभागियों के साथ रोग निगरानी कार्यशालाएं भी शामिल थीं।

बैठक से पहले, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और रोग पूर्वानुमान के लिए जियोमिक सर्विलांस सहित रोग निगरानी पर एक कार्यशाला आयोजित की गई है जिसमें भाग लेने वाले राज्यों के प्रतिभागियों को शामिल करते हुए विचार-मंथन सत्र आयोजित किए गए हैं।

डेयरी किसानों के लिए ₹50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण

विवेकराव पाटिल ने क्षेत्र में लगभग 7,000 पशुओं की गांठदार त्वचा रोग से मृत्यु के बाद दूध उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। बेलगावी जिला इस मुद्दे से बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिससे दूध उत्पादन में कमी आई है क्योंकि किसानों ने अपने पशुधन बेच दिए हैं।

बेलगावी जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक समिति संघ (बीडीसीएमपीएसयू) ने बेलगावी जिले के डेयरी किसानों को पशुधन खरीदने के लिए 50,000 रुपये तक के ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा की है। बीडीसीएमपीएसयू के अध्यक्ष विवेकराव पाटिल ने कहा कि दूध की खरीद और उत्पादन बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (KMF) ने जिले की प्रत्येक सोसायटी को 5 लाख रुपये दिए। BDCMPSU के ऋण कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को मवेशियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अतिरिक्त, मिलावटी दूध के बारे में चिंताओं ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप के अनुरोध को प्रेरित किया।

पशुपालन एवं डेयरी विभाग को जी20 महामारी कोष के तहत 25 मिलियन डॉलर का अनुदान मिलेगा

इंडोनेशिया की G20 प्रेसीडेंसी के तहत स्थापित, महामारी कोष निम्न और मध्यम आय वाले देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर महामारी की रोकथाम, तैयारियों और प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण निवेश का वित्तपोषण करता है।

The Pandemic Fund

जी20 महामारी कोष ने भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (डीएएचडी) द्वारा "महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण" पर प्रस्तुत 25 मिलियन डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

महामारी कोष को पहली कॉल में लगभग 350 अभिरुचि पत्र (ईओआई) और 180 पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें केवल 338 मिलियन डॉलर के मुकाबले कुल 2.5 बिलियन डॉलर से अधिक के अनुदान अनुरोध शामिल थे। महामारी कोष के गवर्निंग बोर्ड ने 20 जुलाई 2023 को छह क्षेत्रों के 37 देशों में भविष्य की महामारियों के प्रति लचीलापन बढ़ाने के उद्देश्य से फंडिंग आवंटन के अपने पहले दौर के तहत 19 अनुदानों को मंजूरी दे दी है।

प्रस्ताव के तहत प्रमुख हस्तक्षेप रोग निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत और एकीकृत करना, प्रयोगशाला नेटवर्क का उन्नयन और विस्तार करना, अंतर-संचालित डेटा प्रणालियों में सुधार करना और जोखिम विश्लेषण और जोखिम संचार के लिए डेटा एनालिटिक्स के लिए क्षमता का निर्माण करना, ट्रांसबाउंड्री के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करना है। पशु रोग और सीमा पार सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग में भारत की भूमिका।

महामारी कोष न केवल महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए अतिरिक्त, समर्पित संसाधन लाएगा। यह बढ़े हुए निवेश को प्रोत्साहित करेगा, भागीदारों के बीच समन्वय बढ़ाएगा और वकालत के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। परियोजना का प्रभाव इस जोखिम को कम करना होगा कि जानवरों (पालतू और वन्य जीवन) से एक रोगज़नक़ निकलकर मानव आबादी में फैल जाएगा जो कमजोर आबादी के स्वास्थ्य, पोषण सुरक्षा और आजीविका को खतरे में डाल देगा। यह परियोजना विश्व बैंक और खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के साथ प्रमुख कार्यान्वयन इकाई के रूप में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के सहयोग से कार्यान्वित की जाएगी।

सरकारी समर्थन और नवाचार के बीच जम्मू-कश्मीर में डेयरी फार्मिंग फल-फूल रही है

नवप्रवर्तन और पर्याप्त सरकारी समर्थन के कारण जम्मू-कश्मीर के कृषि व्यवसाय परिदृश्य में डेयरी फार्मिंग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। भारत सरकार और जम्मू-कश्मीर प्रशासन दोनों ने क्षेत्र में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने पर महत्वपूर्ण जोर दिया है।

इसके अलावा, क्षेत्र में समग्र कृषि विकास कार्यक्रम की शुरुआत आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देकर कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में क्रांति लाने का प्रयास करती है।

डेयरी फार्मिंग के एक स्थानीय अभ्यास से व्यवसाय-उन्मुख उद्यम के रूप में उभरने का श्रेय डिजिटल इंडिया अभियान की सफलता को दिया जा सकता है। इस पहल ने किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया है, जिससे उन्हें देश भर में इनपुट और बाजारों तक पहुंचने और ज्ञान का कुशलतापूर्वक आदान-प्रदान करने में मदद मिली है।

पूरे भारत में डेयरी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड और त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम जैसी राष्ट्रीय पहल शुरू की गई हैं। जम्मू और कश्मीर सरकार की एकीकृत डेयरी विकास योजना ने भी राज्य के डेयरी क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव दिखाया है।

हालाँकि प्रगति पर्याप्त रही है, चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। छोटे और सीमांत किसानों को आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और सीमित दूध शेल्फ जीवन के कारण अक्सर शोषणकारी मूल्य निर्धारण का सामना करना पड़ता है। यह क्षेत्र में मूल्य संवर्धन और डेयरी सहकारी समितियों के विकास की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

डेयरी फार्मिंग के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना एक और उल्लेखनीय पहलू है। महिलाएं, शेखपोरा के एक डेयरी किसान की तरह, जो गायों की एक छोटी इकाई का प्रबंधन करती हैं, अपने घरों में योगदान दे रही हैं और पहचान अर्जित कर रही हैं।

सफ़ेद विकास: डिजिटलीकरण कैसे D2C ब्रांडों की मदद कर सकता है

डिजिटलीकरण पर सरकार के जोर और देश भर में मजबूत इंटरनेट पहुंच की मदद से भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत प्रगति पर है। रेडसीर की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय ई-कॉमर्स 27 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़कर 2026 तक 163 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, जो इसी अवधि में खुदरा बाजार की वृद्धि का तीन गुना है। कृषि एवं कृषि उत्पाद इसके मुख्य घटक हैं

भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, जो प्रति वर्ष 160 मिलियन टन से अधिक दूध का उत्पादन करता है, जिससे डेयरी उद्योग 100 बिलियन डॉलर से अधिक का हो जाता है और 70 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। डिजिटलीकरण इस क्षेत्र के परिवर्तन की कुंजी है और चूंकि डी2सी कंपनियां इस संदर्भ में उपभोक्ता-सामना के विकास का नेतृत्व करती हैं, इसलिए उपलब्ध तकनीक का उनका उपयोग और लाभ डेयरी किसानों के भाग्य और भविष्य के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है।

हालाँकि, डिजिटलीकरण इन चुनौतियों से निपटने और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करने के लिए D2C (निदेशक-से-उपभोक्ता) डेयरी ब्रांडों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहा है। डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर, डी2सी ब्रांड दूध संग्रह और प्रसंस्करण की दक्षता में सुधार कर सकते हैं, किसानों को बेहतर बाजारों तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं और उन्हें अधिक पारदर्शी मूल्य निर्धारण प्रदान कर सकते हैं।

देश के कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 8 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखने वाले प्रमुख आर्थिक चालक डेयरी उद्योग के साथ प्रत्याशित वृद्धि। हालाँकि, भारत में डेयरी किसानों को पारंपरिक रूप से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिनमें कम उत्पादकता, कम कीमतें और बाजारों तक सीमित पहुंच शामिल है।

केंद्र ने पैक्स स्थापित करने के लिए 1.24 लाख पंचायतों की पहचान की

केंद्र ने 1.24 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों की पहचान की है, जहां या तो कोई पैक्स या डेयरी सहकारी समिति या दोनों नहीं हैं, जहां वह अगले दो वर्षों में बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (एम-पैक्स) की स्थापना की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी।

चूंकि मॉडल उपनियमों को पहले राज्यों को इसे अपनाने के अनुरोध के साथ प्रसारित किया गया था, उनके द्वारा स्वीकृति से देश में अधिक एम-पैक्स बनाने में मदद मिलेगी। मंगलवार को 2,000 पैक्स को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया। “जब तक उपनियमों में संशोधन नहीं किया जाता है, मौजूदा पीएसीएस में से कई अपने व्यवसाय का विस्तार करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, भले ही सरकार उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे। एक विशेषज्ञ ने कहा, नए पीएसीएस की स्थापना करना आसान है क्योंकि उन सभी से मॉडल उपनियमों को अपनाने की उम्मीद की जाती है। एक विशेषज्ञ ने कहा कि मौजूदा पीएसीएस में से कई ने अपने उपनियमों में उल्लिखित व्यवसाय के क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया है और ज्यादातर ऋण और कृषि गतिविधियों तक ही सीमित हैं।

सूत्रों ने कहा कि देश की 2,69,364 ग्राम पंचायतों में से 96,405 पंचायतें ऐसी थीं जहां न तो कोई पैक्स है और न ही कोई डेयरी सहकारी समितियां, सहकारिता मंत्रालय द्वारा डेटाबेस बनाने के प्रयास के बाद। सूत्रों ने कहा कि इसके अतिरिक्त, 27,954 पंचायतें हैं जहां मंत्रालय को डेयरी सहकारी समिति का अस्तित्व मिला है, लेकिन वहां कोई पैक्स नहीं है। इसके अलावा, तटीय क्षेत्रों में 680 पंचायतें हैं, जहां केंद्र को मत्स्य पालन सहकारी समितियां बनाने की संभावना दिखती है क्योंकि वहां कोई भी सहकारी समितियां मौजूद नहीं हैं।

शीर्षक: भारत में डेयरी उद्यमिता की क्षमता को उजागर करना: सतत विकास का मार्ग

परिचय:

भारत में डेयरी उद्यमिता की अपार संभावनाएं हैं, यह देश अपनी समृद्ध डेयरी विरासत के लिए जाना जाता है। हालाँकि, विशाल संभावनाओं के बावजूद, एक संपन्न उद्यम के रूप में डेयरी का विकास अपेक्षाकृत धीमा रहा है। इस ब्लॉग में, हम वर्तमान स्थिति, इसके कम उपयोग के कारण, डेयरी उद्यमिता के विभिन्न क्षेत्र, उभरते उद्यमियों के लिए सरकारी योजनाएं, मौजूदा अंतराल और भारत में डेयरी कौशल उत्कृष्टता केंद्र (सीईडीएसआई) द्वारा निभाई जा सकने वाली महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाएंगे। उन अंतरालों को पाटना।

भारत में डेयरी उद्यमिता की वर्तमान स्थिति:

डेयरी उत्पादों की विविध रेंज के साथ भारत विश्व स्तर पर सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। हालाँकि, अधिकांश डेयरी क्षेत्र में अभी भी छोटे पैमाने के किसानों का वर्चस्व है, जिससे उद्यमशीलता उद्यमों की वृद्धि सीमित है। हाल के आंकड़ों के अनुसार, भारत में डेयरी उत्पादन का केवल एक अंश ही संसाधित या मूल्यवर्धित किया जाता है, जो डेयरी उद्यमिता की अप्रयुक्त क्षमता को दर्शाता है।

डेयरी उद्यमिता में बाधा डालने वाली चुनौतियाँ:

- **ज्ञान और कौशल की कमी:** सीमित तकनीकी विशेषज्ञता और आधुनिक डेयरी प्रथाओं का अपर्याप्त अनुभव इच्छुक उद्यमियों के विकास में बाधा डालता है।
- **पूंजी तक पहुंच:** अपर्याप्त वित्तीय संसाधन और ऋण तक सीमित पहुंच डेयरी उद्यमों की स्थापना और विस्तार को प्रतिबंधित करती है।
- **बुनियादी ढाँचा और प्रौद्योगिकी अंतराल:** पुराना बुनियादी ढाँचा, अपर्याप्त कोल्ड स्टोरेज सुविधाएँ और आधुनिक तकनीक की कमी डेयरी संचालन की दक्षता और पैमाने में बाधा डालती है।
- **बाज़ार संपर्क**: विश्वसनीय बाज़ारों तक पहुँचने और मूल्य श्रृंखला स्थापित करने में कठिनाइयाँ डेयरी उद्यमियों की वृद्धि और लाभप्रदता में बाधा डालती हैं।

डेयरी उद्यमिता के विभिन्न क्षेत्र:

- दू**ध प्रसंस्करण और मूल्य वर्धित उत्पाद:** पनीर, दही, मक्खन और आइसक्रीम जैसे उत्पादों के लिए दूध प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करना।
- डे**यरी फार्मिंग:** दूध उत्पादन और नस्ल सुधार के लिए आधुनिक डेयरी फार्मों की स्थापना और प्रबंधन।
- **डेयरी उत्पाद वितरण:** शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी उत्पादों की आपूर्ति के लिए कुशल वितरण नेटवर्क का निर्माण।
- **प्रौद्योगिकी और उपकरण:** नवीन डेयरी प्रौद्योगिकी और उपकरण का विकास और निर्माण।

डेयरी उद्यमियों को सहायता देने वाली सरकारी योजनाएँ:

डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डीईडीएस): आधुनिक डेयरी फार्म और प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई): डेयरी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास और क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई): सूक्ष्म और लघु डेयरी उद्यमियों के लिए ऋण तक पहुंच की सुविधा प्रदान करती है।

अंतरालों को पाटना: डेयरी उद्यमिता में सीईडीएसआई की भूमिका:

सीईडीएसआई भारत में मौजूदा कमियों को दूर करने और डेयरी उद्यमिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- **क्षमता निर्माण और कौशल विकास:** सीईडीएसआई आधुनिक डेयरी प्रथाओं, मूल्य संवर्धन और व्यवसाय प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, इच्छुक उद्यमियों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करता है।
- **तकनीकी प्रगति:** सीईडीएसआई डेयरी क्षेत्र में उत्पादकता और दक्षता में सुधार के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और उपकरणों को पेश करने के लिए अनुसंधान संस्थानों और उद्योग विशेषज्ञों के साथ सहयोग करता है।
- **मार्केट लिंकेज और मेंटरशिप:** सीईडीएसआई उभरते उद्यमियों के लिए बाजार लिंकेज की सुविधा प्रदान करता है, उन्हें संभावित खरीदारों, प्रोसेसर और खुदरा विक्रेताओं से जोड़ता है। यह उद्यमियों को उद्योग की चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए सलाह और मार्गदर्शन भी प्रदान करता है।
- **वकालत और नीति सिफारिशें:** सीईडीएसआई सहायक नीतियों, सुधारों और वित्तीय प्रोत्साहनों की वकालत करने के लिए नीति निर्माताओं और हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ता है जो डेयरी उद्यमिता के विकास को बढ़ावा दे सकते हैं।

निष्कर्ष:

भारत में डेयरी उद्यमिता में सतत विकास की जबरदस्त संभावनाएं हैं। कौशल विकास, वित्त तक पहुंच, बेहतर बुनियादी ढांचे और बाजार संबंधों के माध्यम से चुनौतियों का समाधान करके, यह क्षेत्र फल-फूल सकता है। सीईडीएसआई जैसे संगठनों की सक्रिय भागीदारी और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर, इच्छुक डेयरी उद्यमी अवसरों का लाभ उठा सकते हैं, अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकते हैं।

सीईडीएसआई ने डब्ल्यूडब्ल्यूएफ द्वारा समर्थित, राजस्थान में महिला दूध उत्पादक कंपनी के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया

सीईडीएसआई ने महिला दूध उत्पादक कंपनी के सहयोग से 22 से 24 अगस्त तक राजस्थान के अलावर जिले में दूध उत्पादकों के लिए तीन दिवसीय प्रमाणित क्षमता निर्माण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन किया है। इस कार्यक्रम को वर्ल्ड वाइड फंड (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) द्वारा समर्थित किया गया था, जिसका उद्देश्य डेयरी किसानों की उत्पादकता और लाभप्रदता को बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाना था। 35 किसानों की सक्रिय भागीदारी के साथ, प्रशिक्षण में उन्नत डेयरी खेती प्रथाओं, दूध की गुणवत्ता आश्वासन, जलवायु लचीला डेयरी, दूध उत्पादकता में सुधार, और वित्तीय प्रबंधन और बाजार लिंकेज सहित विभिन्न प्रमुख विषयों को शामिल किया गया। सीईडीएसआई के प्रख्यात विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों की विशिष्ट आवश्यकताओं और प्रश्नों के समाधान के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक समाधान प्रदान किए। कार्यक्रम का सफल समापन अलवर में डेयरी किसानों को सशक्त बनाने और क्षेत्र में टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने, कृषि क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

हम कौन हैं?

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत भारतीय कृषि कौशल परिषद (ASCI) के तत्वावधान में काम करने वाली एक स्वायत्त संस्था "भारत में डेयरी कौशल के लिए उत्कृष्टता केंद्र (CEDSI)", किसानों की आजीविका के सशक्तिकरण और बेहतरी में मदद करने के लिए, वेतनभोगी कर्मचारी, और डेयरी मूल्य श्रृंखला में अन्य हितधारक।

सीईडीएसआई सदस्यता उद्योग के नेताओं, नीति निर्माताओं, विकास चिकित्सकों, डेयरी वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, छात्रों और किसानों को डेयरी उद्योग के लिए आसन्न महत्व के मुद्दों पर बहस और चर्चा करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगी।

CEDSI : रिविविंग स्किल्स एंड जनरेटिंग लाइवलीहुड

किसानों/छात्रों/उद्यमियों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

- डेयरी किसान / उद्यमी
- डेयरी फार्म पर्यवेक्षक
- डेयरी कार्यकर्ता
- पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता
- कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन
- पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक
- पशु चिकित्सा नैदानिक सहायक
- बछड़ा पालन
- कृषि उपकरण तकनीशियन
- डेयरी फार्म अर्थशास्त्र और प्रबंधन
- उद्योग संरेखित प्रमाणन कार्यक्रम (बेरोजगार युवा और छात्र)

एफपीओ उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम

- उत्पाद प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं पर एफपीओ सदस्य अभिविन्यास।
- एफपीओ मार्केट लिंकेज
- एफपीओ शासन
- एफपीओ लेखा

डेयरी कॉरपोरेट्स और सहकारी समितियों के लिए प्रमुख कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

- चिलिंग प्लांट तकनीशियन
- बल्क मिल्क कूलर ऑपरेटर
- ग्राम स्तरीय दुग्ध संग्रह केन्द्र पर्यवेक्षक
- दूध परीक्षक
- ग्रीन हाउस गैसों का शमन
- दूध की गुणवत्ता आश्वासन
- मिल्क डिलीवरी बॉय
- दूध खरीद और इनपुट पर्यवेक्षक
- डेयरी उद्योग में अपशिष्ट प्रबंधन
- चारा और चारा प्रबंधन
- स्वच्छ दूध उत्पादन
- निर्णय समर्थन प्रणाली / डेटा विश्लेषिकी

सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर डेरी स्किल्स इन इंडिया